AAE –1 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

अक्तूबर, 2014

सार लेखन, प्रारूप और मसौदा

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

टिप्पणियां :

(1) सार और प्रारूप तैयार करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करते समय परीक्षार्थी द्वारा उन्हें समझने और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे छोटे वाक्यों में व्यक्त करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गद्यांश को चयनित रूप में दोहरा दे।

(2) इस प्रश्न पत्र में **7** प्रश्न और **4** पृष्ठ हैं।

(3) सभी प्रश्न **अनिवार्य** हैं।

1. निम्नलिखित गद्यांश का सार लिखिए और उसका एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए: *(25 अंक)*

हमारे देश में स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा-प्रणाली मुख्यतः निम्न स्तरीय है। यह दुरवस्था इस शिक्षा प्रणाली के ही कारण है, किसी अन्य वजह से नहीं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली इस तरह रची गई है कि इसमें से सुयोग्य शिक्षित वर्ग तैयार नहीं हो पाता। जब तक हम इस सच्चाई का सामना नहीं करते, तब तक इस शिक्षा प्रणाली से ऐसा ही शिक्षित वर्ग निकलता रहेगा जिसे किसी रोज़गार में नहीं लगाया जा सकेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली के तीन अंग हैं। सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त और निजी संस्थाएं। केंद्रीय स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं जैसे कि आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय ठीक चल रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत अच्छे विद्यार्थी दाख़िला लेते हैं और उन्हें पर्याप्त वित्त साधन उपलब्ध होते हैं। राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही और उनसे सहायता प्राप्त अधिकतर संस्थाओं का स्तर गिर रहा है। शिक्षा संबंधी पूरी न हो रही ज़रूरतों और सरकारी एवं सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं के पतन से घबराकर आने वाले विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी संस्थाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इनमें से भी अधिकतर संस्थाएं स्तरीय नहीं हैं।

सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में निकृष्ट संस्थाओं की हालत के चलते, निश्चित रूप से परीक्षा पास करने के लिए प्राइवेट ट्यूशनों का सिलसिला चल निकला है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अधिकतर संस्थाओं में नाममात्र का पठन-पाठन होता है। इसकी वजह से कुछ और तरह के परिणाम भी सामने आते हैं। शिक्षक, विशेषकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्य कर रहे शिक्षक, दूसरे व्यवसाय के तौर पर ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं या कोई और कार्य करने लगते हैं। सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं में, हालांकि शिक्षकों को तो अच्छा-खासा वेतन मिलता है, लेकिन संस्थाओं को चलाने के लिए वित्त साधन कम होते हैं। शिक्षा-प्रणाली पर सरकारी शिकंजा मज़बूत है। ऐसी निरर्थक प्रणालियां चल रही हैं जिनसे मुख्यतः शिक्षकों की नियुक्ति में देरी होती है। सरकार ऐसी है जो लाइसेंस राज चला रही है और ऐसे नियम बना रही है जिनका उद्देश्य तो गुणवत्ता में सुधार लाना है, लेकिन इनसे केवल लागत ही बढ़ती है और विलम्ब होता है, प्रबंधन का ध्यान शिक्षापरक न होकर केवल धनार्जन पर है, शिक्षक ऐसे हैं जो कार्य नहीं करना चाहते हैं या स्वयं को नवीनतम जानकारी से विमुख रखते हैं तथा विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं न कि ज्ञान।

विश्वविद्यालयों की प्रशासन-व्यवस्था और उनमें पढ़ाने हेतु चुने गए शिक्षकों के चलते ऐसे हालात हो गए हैं जिनके कारण विश्वविद्यालय शिक्षाविदों की बजाय राजनीतिज्ञों के नियंत्रण में आ गए हैं। विश्वविद्यालय अक्सर शैक्षणिक मानकों में ढील दे देते हैं ताकि कॉलेज पर्याप्त सुविधाओं के बिना भी कार्य कर सकें। इसके साथ ही, मूल्यांकन प्रक्रिया भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि निकृष्ट शिक्षकों का एक वर्ग ही आमतौर पर धुआंधार रफ्तार से मूल्यांकन करता है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) (RUSA) नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कॉलेजों को किए जाने वाले धनराशि के आवंटन का अधिकांश राज्य सरकारों के पास चला जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि शिक्षा संस्थाएं कुप्रबंध का शिकार होंगी एवं उनका नियंत्रण अधिकांश धन बटोर लेने वाले नेताओं के पास होगा। निःसंदेह इस सारी मनमानी का चरम बिन्दु था - दिल्ली विश्वविद्यालय का चार-वर्षीय अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम। इन सबसे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ईमानदार संस्थाओं को काम करने में मुश्किल हो रही है और बेईमान संस्थाएं फल-फूल रही हैं।

तथापि, एक अच्छा तरीका भी है और हम ऐसा विश्वासपूर्वक कहते हैं क्योंकि हम सरकारी सहायता प्राप्त ए श्रेणी की संस्थाएं चलाते हैं। मूलतः, हमारे विचार से इसका समाधान यह है कि पहले तो शिक्षा पर से सरकार का कड़ा नियंत्रण हटा दिया जाए। किसी भी संस्था को आरम्भ करने और इसके विस्तार का निर्णय संस्थाओं, खासकर

ऐसी संस्थाओं पर छोड़ दिया जाए जिनका रिकार्ड अच्छा रहा हो। दूसरे, विश्वविद्यालयों में 'निर्वाचकीय' (इलेक्टॉरल) संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाए तथा 'शिक्षाविद' उप-कुलपतियों को शक्ति संपन्न बनाया जाए। तीसरे, सरकारी सहायता ए श्रेणी की संस्थाओं को प्रदान की जाए और अच्छा कार्य न करने वाली संस्थाओं को दी जा रही सरकारी सहायता बन्द की जाए। चौथे, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप की तरह शिक्षकों के चयन की कार्यावधिक ट्रैक विधि अपनाई जाए। वर्तमान में, उन्हें केवल एक वर्ष के पश्चात ही स्थायी कर दिया जाता है। शिक्षा की शासन व्यवस्था के घटिया स्तर के चलते, अच्छे शिक्षकों की शिक्षण से पूरी तरह विमुख होने की भी संभावना है। पांचवें, स्कूलों से विश्वविद्यालय स्तर तक की संस्थाएं आरम्भ करने अथवा उन्हें सहायता प्रदान करने के कार्य में कार्पोरेट सेक्टर को शामिल किया जाए। उन्हें इस प्रयोजन हेतु अपनी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) धनराशि का उपयोग करना चाहिए।

उपेक्षित वर्गों में शिक्षा के प्रति ललक साफ दिखाई दे रही है। शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता का आधार है और वे इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके लिए बड़े त्याग कर रहे हैं। हमें उनका विश्वास भंग नहीं करना चाहिए। सत्ता में नई सरकार आने के साथ, आइए हम सब यह आशा करें कि शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार होगा। जिस तरह का सुधार वर्ष 1991 में उद्योग क्षेत्र में हुआ था, शिक्षा प्रणाली में भी इसी प्रकार का सुधार काफी समय से अपेक्षित है।

2. उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के शब्दों की संख्या लगभग 50 से 75 तक होनी चाहिए।

(5x3 = 15 अंक)

(क) 'हमारे देश में स्कूलों से विश्वविद्यालयों तक शिक्षा-प्रणाली मुख्यतः निम्न स्तरीय है, इस तर्क के समर्थन में दो कारण लिखें।

(ख) वे सुधार कौन से हैं जिनसे भारत की शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी? कोई तीन सुधार सुझाएं।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी कौन सी नई योजना है जिससे उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह किस रूप में होगा?

3. भारत में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने हेतु सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाने वाले अर्ध-शासकीय पत्र का मसौदा तैयार करें।

(20 अंक)

4. "वर्तमान सरकार द्वारा समय की पाबंदी पर जोर देने से सरकारी काम-काज की कार्यक्षमता और दक्षता में किस हद तक सुधार होगा?" लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखें ।

(25 अंक)

5. निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक-एक शब्द लिखें - *(5 अंक)*
   (i) जो कल्पना से परे हो।
   (ii) आलोचना करने वाला।
   (iii) जो मृत्यु के समीप हो।
   (iv) जो आसानी से मिल सके।
   (v) जो तीनों कालों को जानता हो।

6. (क) निम्नलिखित के लिए तीन-तीन पर्यायवाची लिखें- *(3 अंक)*
   (i) ईश्वर
   (ii) अग्नि
   (iii) ऊँचा

   (ख) निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें- *(2 अंक)*
   (i) आरोह
   (ii) अल्पसंख्यक

7. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखें और उनका वाक्यों में प्रयोग करें - *(5 अंक)*
   (i) अक्ल चकराना।
   (ii) ईंट का घर मिट्टी होना।
   (iii) इस हाथ से ले उस हाथ दे।
   (iv) एक टांग पर खड़ा रहना।
   (v) कंचन बरसना।

AAE – 1 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

OCTOBER, 2014

PRECIS AND DRAFT

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

Note : 1. While evaluating the question on précis and drafting, the candidates would be evaluated for their understanding and ability to express the same in short sentences using simple words. He would not be expected to reproduce the passage selectively.
2. This question paper contains **7** questions and **4** pages.
3. All the questions are **compulsory**.

1. Write a précis of the following passage and give a suitable title: *(25 marks)*

The education system in our country is largely dysfunctional, from schools to universities. And this dysfunctionality is because of the system, not despite it. Our system is now designed to produce bad quality. Unless we face up to this fact, we will continue to produce unemployables. There are three wings of the system. Government run, Government aided and private. Government run institutions at the central level like IITs and central universities are working well because they get very good students and are well funded. State Government run and aided insitutions are mostly declining. Private ones are profiferating in quantity to meet the unmet need- and cater to those running away from collapsing Government run and aided system-but are also mostly of poor quality.

In response to poor quality institutions in both Government and private sectors, private tutions have become the way to ensure

clearing of exams. Consequently, in most institutions little teaching or learning is going on. This sets in motion its own set of consequences. Teachers, especially in Government and Government aided institutions, indulge in a second vocation of tuitions or something else. In aided institutions, though the salaries of the teachers are good, funds for running the institutions are scarce. Government stranglehold on education is complete. Irrelevant systems exist which largely delay the appointment of the teachers. Government running a licence raj and making rules that are supposed to improve quality but only increase costs and cause delays, management who are not education but money minded, teachers who do not want to work or upgrade themselves and students who are seeking degrees, not learning.

University governance structures and the teachers being elected for them have led to universities being controlled by the politicians rather than academicians. Universities often dilute the academic standards so that colleges can function without adequate facilities. Also, evaluation is error prone because a coterie of bad teachers is usually doing the evaluation at breakneck speed.

There is a new scheme-Rashtriya Ucchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) that would move the bulk of allocation of funds to colleges from UGC to State Governments. This may result in badly run institutions controlled by politicians cornering most of the funds. The mother of all whimsicality of course was the four year undergraduate course at Delhi University. All this has created a situation where honest institutions find it hard to operate and dishonest institutions flourish.

There is, however, a way forward. And we say this with confidence because we run Government aided 'A' grade institutions. Essentially, the soluctions in our view lie in, first,

lifting the heavy hand of the Government from education. Decision on starting and expanding an institution should be left to the institutions, especially for instituitions with a good track record. Second, disband 'electrol' institutions in universities and empower 'academic' vice-chancellors. Third, give Government aid to A grade institutions and stop giving it to non performing institutions. Fourth, move to a tenure track mode of selecting teachers as in US and Europe. Presently, they are simply confirmed after a year. Given the bad quality of governance, this has the potential of turning away good teachers from teaching altogether. Fifth, get the corporate sector involved in starting or supporting institutions from schools to universities. They should use their Corporate Social Responsibility (CSR) funds for this purpose.

A hunger for education amongst the disadvantaged is palpable. Education is the root for social mobility. And they are going to great lengths for it, making great sacrifices for it. We must not let them down. With a new dispensation in power, let us hope there is serious reform of the education system. One, like that done to industry in 1991, is long overdue.

2. Answer the following questions on the basis of the passage above. The answer should be approximately in 50 to 75 words each.

(5x3=15 marks)

(a) 'The education system in our country is largely dysfunctional, from schools to universities', give two reason to support this argument.

(b) What are the reforms that would improve the education system in India? Suggest any three reforms.

(c) What is the new scheme launched by the Central Government that would affect the quality of higher education adversely and how?

3. Draft a D.O. letter from the Secretary, Department of Higher Education to the Chairman, University Grants Commission to devise a policy roadmap to imporve the standards of higher education in India. *(20 marks)*

4. "How far the current Government's emphasis on punctuality will improve the productivity and efficiency of Government functioning?" please comment in approximately 150 words. *(25 marks)*

5. Complete the following sentences with appropriate prepositions. *(5 marks)*

   (i) Do not fail ..... learn your lessons.
   (ii) This is the pen that she has been searching.....
   (iii) She put the book..... her pillow.
   (iv) Turn left ..... the next crossing.
   (v) He was happy to be..... his friends again.

6. Fill in the blanks with correct conjunctions. *(5 marks)*

   (i) He has been ill ..... he came here.
   (ii) He is clever .....his brother.
   (iii) Walk quickly..... you will miss the bus.
   (iv) He is rich..... he is discontented.
   (v) The father..... the son was arrested.

7. Use appropriate form of verb. *(5 marks)*

   (i) Please sit at the table when you..... (eat)
   (ii) The old man was..... by some strangers with a stick. (beat)
   (iii) Alms are..... to the beggars. (give)
   (iv) The cattle are..... in the field. (graze)
   (v) Dholu will ..... the pony. (bring)